भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-421

उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

उच्च शिक्षा में लखपति दीदी पहल का एकीकरण

†*421. **श्री राजमोहन उन्नीथन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लखपति दीदी पहल को उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल के किसी विश्वविद्यालय को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के विकास के लिए चुना गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च शिक्षा के विस्तार में क्षेत्रीय समानता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“उच्च शिक्षा में लखपति दीदी पहल का एकीकरण” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 421 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): 'लखपति दीदी' पहल 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक परिणाम है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) के सहयोग से लागू किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना तथा ग्रामीण परिवारों को 'स्वयं सहायता समूहों' (एसएचजी) के रूप में संगठित करके उनका सामाजिक और आर्थिक समावेशन करना है। 'लखपति दीदी' पहल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों तक दीर्घकालिक आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित कर सकें। यह एक समुदाय-आधारित आजीविका कार्यक्रम है जिसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से लागू किया जाता है और यह कार्यक्रम व्यावहारिक, अनौपचारिक अधिगम के साथ-साथ उद्यमशीलता से जुड़े कौशलों को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को पूर्ण करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने “भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश” उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के कुलपतियों, निदेशकों, प्रधानाचार्यों, संकाय सदस्यों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के अनुभव को बढ़ावा देना, विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना, गरीबी के कारणों का विश्लेषण करना और बेहतर अधिगम तथा समाधान के लिए कक्षा ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों आईआईएम आदि जैसे केंद्र प्रशासित उच्च शिक्षा संस्थान महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय ‘उन्नत भारत अभियान’ (यूबीए) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम भी चलाता है। इसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को विशेष रूप से समाज और गांवों से जोड़ना है ताकि छात्र और संकाय उस क्षेत्र की प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक विशेषताओं के व्यावहारिक अनुभव से सीख सकें, ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकें और कक्षा में शिक्षाविदों के अलावा ग्रामीण लोगों के पारंपरिक ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को भी समृद्ध कर सकें। यूबीए में 4806 संस्थाएंन भाग ले रही हैं तथा ~23000 भागीदार गांवों में काम कर रही हैं।

(ख): केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को सहयोग प्रदान कर चुनौती मार्ग के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आस-पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थाएं, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

एक परामर्शात्मक प्रक्रिया के माध्यम से योजना की विस्तृत संरचना को अंतिम रूप दी जाएँगी जिसमें इसके कार्यान्वयन मॉडल, प्रमुख घटक, प्राथमिकता वाले क्षेत्र और संस्थागत व्यवस्थापन शामिल हैं। बड़े पैमाने पर, प्रस्तावित विश्वविद्यालय टाउनशिप को विश्व-स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान अवसंरचना प्रदान करने पर विचार किया गया है जिसमें नवाचार और उद्भवन सुविधाएँ, उद्योग साझेदारियाँ तथा दीर्घकालिक शहरी सुविधाएँ शामिल होंगी।

स्थानों का चयन उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, संपर्क क्षमता, क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकताओं, उद्योग से जुड़ने की संभाव्यता, संतुलित क्षेत्रीय विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

(ग): शिक्षा समवर्ती सूची में है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार में क्षेत्रीय निष्पक्षता को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे और अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलना, वर्ष 2014 से 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं; छात्रों जिनमें अल्पसेवित क्षेत्रों के छात्र शामिल है, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं को लागू करना; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले उच्च शिक्षा संस्थाओं (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मानकों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति देना; छात्रों को आसानी से अपने अधिगम पथ के बारे में निर्णय लेने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत आवश्यक लचीलापन और समुचित निर्गम के साथ-साथ प्रवेश का विकल्प प्रदान करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति देना; एक शैक्षणिक वर्ष में दो दाखिला चरणों के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुमति देना; स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) प्लेटफॉर्म जो कई अध्ययन विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों के लिए कभी भी, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना, स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की

अनुमति देना; तथा 13 भाषाओं में जेईई, एनईईटी (यूजी) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) परीक्षाएं आयोजित करना और विशेष रूप से स्थानीय / ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

एनईपी 2020 के अनुरूप, सरकार ने शैक्षणिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। पीएम-उषा के तहत, फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर फोकस जिलों की पहचान की जाती है जिनमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या अनुपात और नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवण जिला आदि शामिल हैं।

बजट घोषणा 2025-26 के अनुसरण में, सरकार ने आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी है जिस पर कुल परिव्यय 11,828.79 करोड़ रुपये होगा जिससे 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ होगी। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर के लिए शैक्षणिक और छात्रावास संबंधी अवसंरचना के विस्तार और अनुसंधान पार्क के विकास के लिए कुल 1942 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पोर्टल के अनुसार, देश में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं, महाविद्यालयों और स्वचलित संस्थाओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 1395, 53197 और 16577 हो गई। एआईएसएचई पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में राज्य-वार डेटा https://dashboard.aishe.gov.in/hedirectory/#/hedirectory पर उपलब्ध है।

*****